



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CE
11/10/85

सं० 365]
No. 365]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 1985/श्रावण 7, 1907
NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 1985/SRAVANA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली 29 जुलाई 1985

New Delhi, the 29th July, 1985

दा आ. 557(अ) —केंद्रीय सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अनुसरण से, मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड, मिराज के युनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन की स्कीम के संबंध में, जो उक्त उपधारा के उपबंधों के अर्धीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई है, 30 जुलाई, 1985 को विहित तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

S.O. 557(E)—In pursuance of sub-section (7) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies the 30th July, 1985 as the prescribed date in relation to the scheme for the amalgamation of the Miraj State Bank Limited Miraj, with Union Bank of India which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of the said sub-section.

[सं. फा० टीएम/1/85-बीओ-III]

[No. F. TS 1/85-B.O. III]

का. आ. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार ने बैंकर्स अधिनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन, मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड, मिरज के संबंध में उक्त धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थानन आदेश दिया है।

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड के सम्मेलन की स्कीम तैयार की है।

और रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उक्त स्कीम का प्राप्ति संबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात् और उक्त स्कीम की वास्तव प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् वह स्कीम उपान्वित की है और उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है।

अब अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें आगे वर्णित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम को मंजूरी दे दी है।

(1) मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड, मिरज अन्तरक बैंक होगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अन्तरिनी बैंक होगा।

(2) ऐसी तारीख से जिस केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करें, (जिसके इसमें इसके पश्चात् विहित तारीख कहा गया है) अन्तरक बैंक के सभी अधिकार, शक्तियाँ, मांग, दावे, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, लाभ, आस्तियाँ और जंगम और स्वावर संपत्ति, जिसके अन्तर्गत भू-धृति के सभी आपत्तियों या पट्टों या करारों द्वारा आरक्षित और उनमें अन्तर्विष्ट भाटकों और अन्य धनराशियों और प्रसविदाओं के अधीन परिमर, जिसके अधीन वे धारित हैं, सभी कार्यालय फर्नीचर, विप्रेक्षित उपकरण, संयंत्र, यंत्र और साधन, बही कागजपत्र लेखन-सामग्री, स्टॉक, अन्य स्टॉक और सामान, सभी स्टॉक विनिधान, शेयर और प्रतिभूतियाँ, हाथ में और अभिवहन में प्राप्य सभी हुण्डिया सभी हाथ की और लेखा की रोकड़ या बैंकों पास निक्षेप लेखा (जिसके अन्तर्गत मांग पर या संक्षिप्त सूचना पर धन भी है), कुलियत, सभी बही ऋण, बंधक ऋण और प्रतिभूतियों के फायदे सहित अन्य ऋण या उनकी कोई प्रत्याभूति अन्तरक बैंक के कारबार के संबंध में सभी अन्य, यदि कोई हों संपत्ति अधिकार और सभी प्रत्याभूतियों के आस्ति संबंधी फायदे, इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्तरित बैंक को अन्तरिनी हो जाएंगे और उनकी सम्पत्ति और आस्तियाँ बत जाएंगे और विहित तारीख से ही अन्तरक बैंक के सभी दायित्व, कर्तव्य और फायदे, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक और रीति

में अन्तरिनी बैंक के दायित्व, कर्तव्य और दायित्वपूर्ण होंगे और बत जायेंगे।

पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी संविदायें, विनियम, बंधपत्र, करार, मुहताबनाम, विधिक प्रतिनिधित्व की मंजूरियाँ और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखतें जो विहित तारीख के ठीक पहले आस्तिकता या प्रभावशील हों, अन्तरिनी बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में इसमें आगे उपबंधित विस्तार तक और रीति में प्रभावशील होंगी और जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेंगी माना अन्तरक बैंक के स्थान पर अन्तरिनी बैंक उसमें पक्षधारक रहा हो, माना वे अन्तरिनी बैंक के पक्ष में जारी की गई हों।

यदि विहित तारीख को अन्तरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकृति की कोई अन्य विधिक कार्यवाही चलित है तो उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तरिनी बैंक के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती और प्रवर्तित की जा सकती।

यदि भारत में बाहर के किसी देश की विधि के अनुसार इस स्कीम के उपबंध उस देश में स्थित किसी ऐसी आस्तियाँ दायित्व को जो अन्तरक बैंक के उपक्रम के भाग हैं, अन्तरिनी बैंक को अन्तरित या उसमें निहित करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखते तो ऐसी आस्तियाँ दायित्व के संबंध में अन्तरक बैंक का कार्यकालाप विहित तारीख से अन्तरिनी बैंक के तत्समय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में स्थित हो जाएगा और वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसी सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो प्रभावी रूप से इसके कार्यकालाप के परिणामाप्त के प्रयोजन के लिए अन्तरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की जा सकती या की जा सकती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा अन्तरण और निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाहियाँ करेगा जो भारत के बाहर किसी ऐसी देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हो और उस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अन्तरक बैंक की आस्तियाँ बतूल कर सकेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा और उसके शुद्ध आगामों का अन्तरिनी बैंक को अन्तरित कर देगा।

(3) अन्तरक बैंक को बहिया बन्द की जाएगी और उनकी तुलना की जाएगी और तुलनपत्र प्रथमतः 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति पर और तत्पश्चात्, विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को कारबार की समाप्ति पर तैयार किया जाएगा तथा तुलनपत्र चाटेंड लेखाकार या चाटेंड लेखाकारी की किसी ऐसी फर्म द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामनिर्दिष्ट की गई हो, संपरीक्षित और प्रमाणित कराये जायेंगे।

पूर्वगामी पैरा के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई अन्तरक बैंक के तुलनपत्र की प्रत्येक प्रति अन्तरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथासंभव नीचे कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी और तत्पश्चात् अन्तरक बैंक से तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखा तैयार करने या उसे सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतिया कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की या तुलनपत्र और लेखा पर विचार करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए वाणिज्य साधारण अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात् अन्तरक बैंक के निदेशक बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 285 की अपेक्षानुसार अधिवेशन करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) I. अन्तरिती बैंक अन्तरक बैंक के परामर्श से निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अन्तरक बैंक की संपत्तियों और आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और दायित्वों की गणना करेगा, अर्थात्—

(क) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विनिधानों का मूल्यांकन विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख की विद्यमान बाजार दरो पर किया जायेगा।

(ख) (i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के प्रयोजन के लिए जारी की गई अधिमूचना में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार विहित रीति में ठीक पूर्ववर्ती तारीख का यथा विद्यमान रूप में किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर-प्रमाणपत्र, ट्रेजरी वचन निशेष प्रमाण पत्र और केन्द्रीय सरकार की लघु वचन योजना के अधीन जारी की गई कोई अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य के आधार पर या उक्त तारीख को नकद प्राप्त मूल्य के आधार पर, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, किया जाएगा।

(iii) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमींदारी उन्मूलन बंधपत्र या अन्य समान प्रतिभूति जिसकी याबत मूल किश्तों में देय है, का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या किसी कारणवश यह माना जाता है कि वह उसका उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करना है या वह अन्यथा उचित नहीं है, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन उतनी रकम पर किया जाएगा जो संदत्त किए जाने वाले बकाया मूल और उसकी व्याज की किस्तों का उस कालावधि को जिसके दौरान ऐसी किश्तें संदेय है, सरकार द्वारा जारी की गयी किसी प्रतिभूति के मूल्य को जिससे प्रतिभूति का संबंध है और जिसकी वैसी ही या लगभग वैसी ही परिपक्वता

है तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त समझा जाता है।

(ग) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य उसके प्रसामान्य बातों से प्रभावित हो जाने के कारण युक्तियुक्त नहीं माना जाता है, वहां विनिधान का मूल्यांकन किसी युक्तियुक्त कालावधि के दौरान उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

(घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर या डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां जारी करने वाले समुत्थान की वित्तीय स्थिति, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा संदत्त लाभों और अन्य मुसंगत बातों का ध्यान में रखते हुए, केवल ऐसे मूल्य को, यदि कोई है, हिमाब में लिया जाएगा जो युक्तियुक्त मूल्य माना जाएगा।

(ङ) दावों की तुष्टि के लिए अर्जित परिसरों और अन्य सभी जगम संपत्तियों और किन्हीं आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर किया जायेगा।

(च) फर्नीचर और फिक्सचर, स्टॉक का लेखन सामग्री और अन्य आम्नियां यदि कोई हों, का मूल्यांकन प्रति वही अधिकथित मूल्य के आधार पर या वसूली योग्य मूल्य के आधार पर, जो भी युक्तियुक्त समझा जाए, किया जाएगा।

(छ) अग्रिमों, जिसके अन्तर्गत क्रय की गई और मितिकाटे पर भुगतान की गई हण्डियों भी है, वही ऋणों और विधिक आस्तियों की संवीक्षा अन्तरिती बैंक द्वारा की जाएगी और प्रतिभूतियों जिनके अन्तर्गत उसके आवक के रूप में धारित प्रत्याभूतियों भी है, अन्तरिती बैंक द्वारा परीक्षित और सत्यापित की जाएगी। तत्पश्चात्, अग्रिम जिनके अन्तर्गत उनके भाग भी है, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् “वे अग्रिम जिन्हें अच्छा और आसानी से वसूली योग्य माना गया है” और “वे अग्रिम, जिन्हें आसानी से वसूली योग्य नहीं माना गया है और/या जिनकी वसूली डूबंत या शंकास्पद है।”

II इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए दायित्वों के अन्तर्गत ऐसे सभी समाश्रित दायित्व भी है, जिनके लिए अन्तरिती बैंक से विहित तारीख का या उसके पश्चात् अपने स्वयं के खर्चों से उचित रूप से पूर्ति करने की आशा या अपेक्षा की जा सकेगी।

III जहां किसी आस्ति का मूल्यांकन विहित तारीख का अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहां वह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, भागतः या पूर्णतः किसी पश्चात्-वर्ती तारीख को वसूली योग्य आस्ति के रूप में माना जायेगा।

किमी आस्ति के मूल्यांकन और/या किसी अग्रिम के वर्गीकरण और/या किसी दायित्व के अवधारण की बाबत अन्तरिनी बैंक और अन्तरक बैंक के बीच कोई असहमति है, तो वह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया जाएगा जिसकी राय अंतिम होगी, परन्तु जब तक ऐसी राय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अन्तरिनी बैंक द्वारा मदी या उसके भाग का मूल्यांकन इस स्कोम के प्रयोजन के लिए अनन्तिस रूप में अपनाया जाएगा।

ऐसा करना आवश्यक होने की दशा में रिजर्व बैंक के लिए ऐसी तकनीकी राय प्राप्त करना आवश्यक होगा जो वह आस्ति की ऐसी किसी मद के मूल्यांकन या दायित्व की ऐसी किसी मद के अवधारण के संबंध में समुचित समझे, और ऐसी राय अधिप्राप्त करने का व्यय अन्तरक बैंक की आस्तियों में से पूर्ण रूप में देय होगा।

पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार आस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण दोनों बैंकों और उसके सदस्यों और लेनदारों पर आवृद्ध कर होगा।

(5) अन्तरक बैंक की सर्वाति और आस्तियों के अन्तरिनी बैंक का अन्तरण होने के प्रतिफल स्वरूप अन्तरिनी बैंक इस ओर निम्नलिखित खंडों में वर्णित विस्तार तक अन्तरक बैंक के दायित्वों का निर्वहण करेगा, अर्थात्—

(क) विहित तारीख तक कर्मचारिवृन्द प्रतिभूति निक्षेप सहित उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो के साथ उस बैंक के पास अन्तरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा जमा की गई कोई धनराशि और विहित तारीख को सभी अन्य बाह्य दायित्व जिसके अन्तर्गत निक्षेप नहीं है, मदत किए जाएंगे या उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित तारीख तक निक्षेप पर देय ब्याज संबंध निक्षेप का भाग माना जाएगा।

(ख) प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी अन्य निक्षेप की बाबत जिसके अन्तर्गत मावधि-निक्षेप, तर्क प्रमाणपत्र, मासिक निक्षेप, माग या संक्षिप्त मुचता पर देय निक्षेप या अन्तरक बैंक के पास कोई अन्य निक्षेप चाहे वे किसी भी नाम से जाने जानें हो और कोई अन्य खाते जो खंड (क) के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिसके अन्तर्गत इस स्कीम के अधीन देय सीमा तक ब्याज भी है, अन्तरिनी बैंक विहित तारीख को संबंधित धारक (कों) के नाम में एक नवमान और वैसा ही खाता खोलेंगा जिसमें विहित तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए पैरा (4) में निर्दिष्ट तथा मूल्यांकित आस्तियों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध आनुपातिक शेयर मूल्य के रूप में जमा करेगा और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त आस्तियों में से वे अग्रिम जो आसानी से बमूषी योग्य नहीं माने गए हैं

या इब्त है या जितनी बमूली जमास्पद है कोई अन्य आस्ति या आस्ति के भाग जो विहित तारीख का मूल्यांकित नहीं है और अन्य रकम जो ऊपर खंड (क) में वर्णित मदाय या उपबंधों के लिए अपेक्षित हैं, अवर्षित किए जाएंगे और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त आस्तियों में अन्तरक बैंक का जारी किए गए तारीख 27 अप्रैल, 1985 के अधिस्थगन आदेश के पैरा 2 के खंड (क) (1) के आधार पर किए गए मदायों की सकलित रकम जोड़ेगा।

परन्तु 27 अप्रैल, 1985 को कारवार की समाप्ति को या उसके पश्चात् और विहित तारीख के पूर्व किसी निक्षेप खाते से किए गए किसी मदाय की गणना इस उप पैरा के अर्दान जमा की जाने वाली रकम के मद्दे की जाएगी और तदनुसार जमा की जाने वाली रकम आनुपातिक शेयर होगी जिसमें ऐसे मदाय की रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु यह और कि जहां अन्तरिनी बैंक का किसी विशेष खाते में की गई प्रविष्टियों के गही होने के बारे में कोई व्यक्तिगत मदेय है तो वह रिजर्व बैंक के अनुमोदन में, ऊपर खंड (ग) के आधार पर उस लेखे में किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा जब तक कि अन्तरिनी बैंक ऐसे खाते में सही अनिषेध अभिनिश्चित नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण

"आनुपातिक" पद में, जहां तक वह इस पैरा में आता है ऐसी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 27 अप्रैल, 1985 को कारवार की समाप्ति पर बकाया देय है (विहित तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख तक देय ब्याज सहित) और जहां तक वह इस स्कीम में अन्यत्र आता है, वे ऐसी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो मदाय या विवरण के समय बकाया देय है

(ग) ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट जमा धनराशि दिए जाने के पश्चात् अन्तरिनी बैंक संभवतः कम से कम विलम्ब में किंतु विहित तारीख से तीन माग तक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् निगम कहा गया है) एक सूची देगा, जिसमें सभी प्रकार से उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, और तत्पश्चात् जब भी उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम निगम से प्राप्त हो अन्तरिनी बैंक उस तारीख या तारीखों में जिसका रकम प्राप्त होती है, सात दिन के अन्दर उस खाते में देय धनराशि के विस्तार तक, उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक खातों में जमा करेगा

परन्तु,—

- (क) यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई खाता बन्द कर दिया गया है या वह ऐसे समय पर जब उस खाते में जमा के लिए रकम निगम से प्राप्त होती है, परिपक्व हो गया है तो उक्त रकम के हकदार व्यक्ति को सदाय अन्तरिनी बैंक द्वारा सकल रूप में किया जाएगा,
- (ख) यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी रकम के हकदार व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका आसानी से पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देय रकम के लिए उपबन्ध स्वयं निगम की बहियों में किया जाएगा और उसका पथक रूप में लेखा दिया जाएगा तथा अन्तरिनी बैंक को किसी रकम का सदाय करना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा जब तक कि रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका पता नहीं चल जाता है और निगम ने अन्तरिनी बैंक के माध्यम से उस व्यक्ति की वास्तव सदाय करने का विनिश्चय नहीं कर लिया है,
- (घ) विहित तारीख का अन्तरिनी बैंक का समादत्त पृजी का संपूर्ण रकम और आरक्षित का इवंत और षकास्पद ऋण के लिए उपबन्ध के रूप में माना जाएगा और अन्तरक बैंक की अन्य आस्तियों में अवधायण और अन्तरक बैंक के सदस्यों के अधिकार अन्तरिनी बैंक के संबंध में ऐसे होंगे जो नीचे पैरा (6) में उपबोधित है।
- (6) निम्नलिखित की वास्तव,—
- (क) पूर्ववर्ती पैरा के खंड (ख) में वर्णित प्रत्येक लेखे की वास्तव उम खंड और खंड (ग) के आधार पर किसी लेखे, यदि कोई है, में जमा न किया गया अतिशेष, और
- (ख) अन्तरक बैंक में प्रत्येक शेयर की वास्तव जिसकी रकम की विहित तारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा या उसकी ओर से शेयर पृजी के मद्धे समादत्त रूप में माना गया था या नीचे (1) के अनुसरण में अन्तरिनी बैंक द्वारा की गई मांग के मद्धे रकम सदन की गई थी, संग्रहण रकम के रूप में माना जाएगा और उसे अन्तरिनी बैंक की बहियों में उस प्रकार दर्ज किया जाएगा आरक्षण के विरुद्ध सदाय निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्,—
- (1) (क) अन्तरिनी बैंक प्रथमतः ऐसे व्यक्ति से जो विहित तारीख को अन्तरक बैंक में आस्थगित शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था (या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होता) ऐसी तारीख या तारीखों में तीन मास के

अन्दर जो विनिर्दिष्ट की जाए या जाएं, ऐसे शेयर या शेयरों और बकाया मांगों, यदि कोई हों, की वास्तव उसके द्वारा असदत्त रह रही अनाहत रकम का सदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात् यदि यह आवश्यक पाया जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो विहित तारीख को, अन्तरक बैंक के माधारण शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था (या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होता) ऐसी तारीख या तारीख में जो विनिर्दिष्ट की जाए, तीन मास के अन्दर ऐसे शेयर या शेयरों या बकाया मांगों, यदि कोई हों, की वास्तव उसके द्वारा असदत्त रह रही अनाहत रकम का सदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

- (ख) अन्तरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यतिक्रम की कालावधि के लिए छह प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित खंड (क) के अधीन देय रकम के सदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी उपलब्ध कदम उठायेगा।

(2) अन्तरिनी बैंक अग्रिमों, क्रय या मितिकांटा किए गए भुगतान हुण्डियों, बही ऋणों और विविध ऋणों और अन्य आस्तियों की वास्तव जो "ऐसे अग्रिमों के रूप में जो आसानी से बसूली योग्य नहीं है और या बसूली के लिए इवंत या षकास्पद" है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या जो ऊपर पैरा 4 के आधार पर विहित तारीख के पश्चात् पूर्णतः या भागतः बसूली योग्य है या हो सकते हैं, के संबंध में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सदाय की मांग और उसे प्रवर्तित कराने के लिए सभी उपलब्ध कार्य-वाही करेगा परन्तु यह और कि किसी ऋण या आस्ति की रकम 50,000 रूपए से अधिक है, तो अन्तरिनी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना,

- (क) ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा या किसी ऐसे ऋण या आस्ति को बट्टे-खाते नहीं डालेगा।

- (ख) उसे अतिरिक्त किन्हीं प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा ली गई किसी आस्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

(3) इसके अतिरिक्त, अन्तरिनी बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ज के साथ और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 543 के साथ भी पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45उ के अधीन अन्तरिनी बैंक के किसी संप्रबर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा नुकसानी के रूप में अधिनिर्णीत की गई रकम यदि कोई हो, की मांग करने और उनका सदाय करवाने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी उपलब्ध कार्य-वाहियां करेगा,

(4) अन्तरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (i), (ii), और (iii) में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की गई वसूलियों में से किसी समाश्रित दायित्व की बाबत, और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी ऐसे दायित्व, चाहे वह समाश्रित हो या अत्याधिक, की बाबत, जिसे उपर्युक्त पैरा (4) के निबंधनों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था और जो विहित तारीख को या उसके पश्चात् उद्भूत हुआ है या जिसका पता चला है, संदाय कर सकेगा या उस सीमा तक, जो पैरा 5 (क) के अधीन उसके लिए किया गया उपबंध अपर्याप्त हो, उपबंध कर सकेगा ;

(5) अन्तरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की गई वसूलियों में से, उस प्रयोजन के लिए उपगत व्यय की और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य व्ययों की, जो उचित समझा जाए, उसमें से कटौती करने और उपर्युक्त खंड (4) के निबंधनों के अनुसार उसमें से रकम विनियोजित करने के पश्चात् या ऐसे अनिशेष, यदि कोई हो, में से, जो ऐसे दायित्वों की सीमा अंतिम रूप में अभिनिश्चित की जाने के पश्चात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित समाश्रित दायित्वों की बाबत उपबंध में से उपलब्ध हो,

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अन्तरिती बैंक द्वारा निगम में प्राप्त रकम और निगम द्वारा उपबंधित रकम, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, और

(ख) ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में, जिनकी बाबत अन्तरिती बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त नहीं की गई है, संग्रहण खाते की बाबत शोध्य रकमों का, और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में, जिनकी बाबत अन्तरिती बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त की गई है या निगम द्वारा उपबंधित की गई, निगम द्वारा किए गए या उपबंधित संदाय की बाबत निगम को उक्त खाते से शोध्य रकमों को उपर्युक्त उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार पहले सदन किए जाने के पश्चात् उनके संग्रहण खाते में उन्हें शोध्य अनिशेष, यदि कोई हो, का संदाय करेगा ;

परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, अन्तरिती बैंक की बाहियों में उपबंधित की जाएगी तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम साधारण विनियम, 1961 के विनियम 22 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से निगम को सदन की जाएगी ।

परन्तु यह और कि अन्तरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट संदाय उस दशा में करेगा,

(i) यदि पैरा (5) के खंड (ख) में उल्लिखित तत्समान या समरूप खाते को बद नहीं किया गया है या

वह उस खाते में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, और

(ii) यदि उक्त खाते को बंद कर दिया गया है या वह नकद भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है ;

(6) उपर्युक्त खंड (5) के उपखंड (क) के निबंधनों के अनुसार निगम को शोध्य रकमों और उस खंड के उपखंड (ख) के निबंधनों के अनुसार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों की श्रेणी आपस में समान होगी, और यदि उनका संदाय पूर्णतः नहीं किया जा सकता तो उनमें समान अनुपात में कमी होगी ;

(7) इस पैरा के खंड (5) में निर्दिष्ट संदाय के लिए जाने या पूर्णतः उपबंधित किए जाने के पश्चात् अन्तरिती बैंक खंड (5) में निर्दिष्ट रकमों के 'उस अनिशेष जो उसके पास उपलब्ध हो, में से, अंतरक बैंक के भूतपूर्व शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो, हेतु ऐसी रीति में और उस सीमा तक, जो नीचे विनिर्दिष्ट है, आनुपातिक संदाय करेगा :

(क) प्रथमतः, सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व अधिमान शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो ;

(ख) द्वितीयतः, सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो, और उसके पश्चात् ,

(ग) तृतीयतः, सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व आस्थगित शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो ;

(घ) उपर्युक्त उपखंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सब रकम को पूर्णतः सदन करने पश्चात् अन्तरिती बैंक के पास बाकी बचे अधिशेष का अंतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के बीच आनुपातिक वितरण किया जाएगा ।

परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त किसी उपखंड में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम शोध्य है या नहीं तो उसमें भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(8) इस पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खाते में शोध्य रकम के बारे में केवल अन्तरिती बैंक का दायित्व उस सीमा तक गणना जाएगा जो इस स्कीम में उपबंधित है ;

(9) विहित तारीख या ऐसी पूर्वतर अवधि में, जो केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, बारह वर्ष के अवसान पर, इस पैरा के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी ऐसी मद का, जो उस तारीख तक वसूल नहीं की जा सकी हो,

मूल्यांकन अन्तरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा और अन्तरिती बैंक, उस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अवधारित कोई रकम, उस पैरा के खंड (iv) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक किसी ऐसी राशि की, जो उपर्युक्त खंड (v), (vi) और (vii) में उपबंधित क्रम और रीति से उस तारीख तक चुकायी जाने से रह गई हो, पहले उसमें से कटौती करके वितरित करेगा।

(x) अन्तरिती बैंक, पूर्ववर्ती खंड (i) (ii) और (iii) में उल्लिखित मदों के कारण बसूल किए गए ऐसे धन को, जिनकी तुरन्त संचाय के लिए, उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की संभावना नहीं है, अपने पास या किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास व्याज वाले निक्षेपों में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हो या जैसा भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश दे, विनिहित करेगा। प्रोद्भूत व्याज को खंड (iv), (v), (vi) और (vii) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए, उनमें उपदर्शित रीति से उपयोजित किया जाएगा।

(7) किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होने हुए भी, पैरा (5) के निबंधनों के अनुसार अन्तरिती बैंक के पास खोले गए गए खाते की बाबत व्याज का संचाय किया जाएगा और उस केवल उन या अगले उत्तरवर्ती पैराओं के उपबंधों के अनुसार ऐसी दरों पर, जो अन्तरिती बैंक अनुज्ञात करे, जमा किया जाएगा।

(8) कोई भी निक्षेपकर्ता या अन्तरक बैंक का अन्य लेनदार, उसके प्रति अन्तरक बैंक के किसी दायित्व की बाबत अन्तरक बैंक या अन्तरिती बैंक से, इस स्कीम द्वारा विहित सीमा के सिवाय, कोई मांग करने का हकदार नहीं होगा।

(9) केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या अन्तरिती या अन्तरक बैंक के खिलाफ किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आणयित हैं।

(10) उत्तरवर्ती पैरा में निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों से निम्न अन्तरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और यह समझा जाएगा कि उन्हें अन्तरिती बैंक द्वारा उसी पारिश्रमिक और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो 27 अप्रैल, 1985 को कार्रवार बंद होने के ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों को लागू थीं।

परन्तु यह कि अन्तरक बैंक के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने अन्तरक बैंक या अन्तरिती बैंक को, उस तारीख के, जिसका यह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया है, ठीक आगामी एक मास के आवासान के पूर्व किसी भी समय अन्तरिती बैंक के कर्मचारी न होने के अपने आणय के बारे में लिखित सूचना द्वारा सूचित किया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन ऐसे प्रतिकर, यदि

कोई हो और ऐसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा-निवृत्ति फायदे के संचाय के लिए हकदार होंगे, जो 27 अप्रैल 1985 को कार्रवार के बंद होने के ठीक पहले अन्तरक बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हों।

परन्तु यह और कि अन्तरक बैंक के ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें अन्तरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है अन्तरिती बैंक के बारे में भी यह समझा जाएगा कि उसने अन्तरिती बैंक की सेवा में रहने के दौरान उनकी छुट्टी की दशा में उस आधार पर छुट्टी प्रतिकर के संचाय का दायित्व लिया है कि उनकी सेवा निरंतर बनी रही है और अन्तरिती बैंक में उनके स्थानांतरण से विच्छिन्न नहीं हुई है।

(11) इस स्कीम में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, विहित तारीख की अन्तरक बैंक के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे और तन्मध्य प्रवृत्त किसी विधि या किसी कारण या संविदा में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति, केवल ऐसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य सेवा-निवृत्ति फायदे के हकदार होंगे, जो 27 अप्रैल, 1985 को कार्रवार के बंद होने के ठीक पहले अन्तरक बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन उन्हें सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हों।

परन्तु यह कि नियोजन की दृष्टि के लिए प्रतिकर, यदि कोई हो, तब तक उसका संबंध सेवा की किसी संविदा के अनिवारित भाग से है केवल वही होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित किया जाए (इस बाबत जिसका अवधारण अंतिम और आवद्धकर होगा)।

परन्तु यह और कि इसमें की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह अन्तरिती बैंक को किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसका नाम इस स्कीम में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसी हैसियत में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अन्तरिती बैंक उचित समझे, पुनर्नियोजन करने में निवारित करती है।

(12) अन्तरिती बैंक, उस तारीख से, जिसको इस स्कीम को मंजूर किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक अवधि के अवसान पर, अन्तरक बैंक के कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक और सेवा के वही निबंधन और शर्तें संचाय या मंजूर करेगा, जो अन्तरिती बैंक के तत्समान बैंक या प्रास्थिति के कर्मचारियों को, अन्तरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के समान या समतुल्य अन्तरक बैंक के उक्त कर्मचारियों के पास अर्हताएं और अनुभव के अधीन रहते हुए, लागू हों।

परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मतभेद उत्पन्न होता है कि उक्त कर्मचारियों में से किसी की अर्हताएं या अनुभव अन्तरिती बैंक के तत्समान बैंक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव के समान या समतुल्य है

या नहीं या वह अन्तरिणी बैंक के बेतनमान में कर्मचारियों का बेतन नियत करने के लिए अपना जाने वाले सिद्धांतों की प्रक्रिया के संबंध में है, तो शंका या मतभेद को भारतीय रिजर्व बैंक को निदिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(13) यथास्थिति, अन्तरक बैंक या अन्तरिणी बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी श्रवण निधि के न्यासी या प्रशासक, विहित तारीख को या उसके पश्चात् यथा संभव शीघ्र, अन्तरिणी बैंक के लिए गठित कर्मचारी श्रवण निधि के न्यासी को,

या अन्यथा, जैसा अन्तरिणी बैंक निदेश दे, अन्तरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सब धन और विनिधान अन्तरित कर देंगे।

परन्तु यह कि ऐसे पश्चात्कर्त्तृ न्यासी, विनिधानों के मूल्य में किसी कमी के लिए, या विहित तारीख के पहले किए गए किसी कार्य उपेक्षा, या व्ययक्रम की बावत दावों नहीं होंगे ।

(14) अन्तरिणी बैंक, ऐसे विवरण और जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित करने के संबंध में समय-समय पर अपेक्षा करे।

(15) अन्तरिणी बैंक, अन्तरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण, ऐसे प्रारूप में और ऐसे कालिक अंतरालों पर, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिदिष्ट करे, अन्तरक बैंक के शेयरधारकों को भेजेगा। ऐसे विवरणों का भेजा जाना तब रोका जाएगा जब रिजर्व बैंक ऐसा निदेश दे ।

(16) किसी ऐसी सूचना या अन्य संसूचना के बारे जिसकी अन्तरिणी बैंक द्वारा दी जाने की अपेक्षा की जाती है, उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसे सम्यक् रूप से दे दिया गया है, यदि अन्तरक बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत पते पर, जब तक कि कोई नया पता अन्तरिणी बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत न हो, प्रेषित की सर्वाधिकृत किया गया है, और उसे पूर्व-संदर्भ सामान्य डाक से भेज दिया गया है, और ऐसी सूचना उसे डाक से डाले जाने के पश्चात् अङ्गतालीस घंटे के अख्यान पर तामील की गई समझी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी ऐसी सूचना या संसूचना को, जो सार्वजनिक हित की हो, एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका परिचलन ऐसे स्थानों पर हो जहां बैंक अपने कारबार का संव्यवहार कर रहा था, विज्ञापित किया जाएगा ।

(17) यदि इस स्कीम के किसी उपबंध का निर्वहन करने समय कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को निदिष्ट किया जाएगा और उसकी राय निश्चायक होगी और अन्तरिणी बैंक और अन्तरक बैंक, दोनों पर तथा इस प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों, निक्षेपकर्त्ताओं और अन्य नेतृत्वों तथा कर्मचारियों पर भी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति

पर, जिसका इन बैंकों में से किसी के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व है, आबद्ध कर होंगे ।

(18) यदि इस स्कीम के उपबंधों का प्रभाव करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, अन्तरक और अन्तरिणी बैंकों को या उनमें से किसी को, ऐसे निदेश, जो इस स्कीम से असंगत नहीं, जारी कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार को, भारतीय रिजर्व बैंक में परामर्श करने के पश्चात् कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो ।

[फा. सं. टी. एम/1/85-बी. आ. III]

जगद केवकर, अपर सचिव

अनुसूची

बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अर्थात् केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड के समामेलन के लिए स्कीम में मूलभूत और उसका भाग रूप अनुसूची

कर्मचारी का नाम	अन्तरक बैंक में पदनाम
1. श्री बी. कृष्णन	सहायक महाप्रबंधक

S.O. 558(E).—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government has made, under sub-section (2) of the said section 45 an Order of moratorium in respect of the Miraj State Bank Ltd., Miraj under sub-section (2) of the said section.

And whereas the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 45 of the said Act has prepared a scheme for the amalgamation of the Miraj State Bank Ltd., Miraj with the Union Bank of India.

And whereas the Reserve Bank after having sent the said scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme has modified that scheme and forwarded it to the Central Government for sanction.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the scheme on and subject to the terms and conditions hereinafter mentioned :

(1) The Miraj State Bank Ltd., Miraj shall be the transferor bank and the Union Bank of India shall be the transferee bank.

(2) As from the date which the Central Government may specify for this purpose under sub-section (7) of section 45 of the said Act (hereinafter referred to as the prescribed date) all rights, powers claims,

demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums or money and covenants reserved by or contained in the leases or agreements under which they are held, all office furniture, loose equipment, plant, apparatus and appliances, books, papers, stocks of stationery, other stocks and stores all investments in stocks, shares and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit account (including money at call or short notice) with banks, bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefit of securities, or any guarantee therefor, all other, if any, property rights and assets benefit of all guaranties in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of this scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of, the transferee bank; and as from the prescribed date all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the manner provided hereinafter.

Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending, the same shall not abate, or be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall subject to the other provisions of this scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

If according to the laws of any country outside India the provisions of this scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such assets or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the chief executive officer for the time being of the transferee bank and the chief executive officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively winding up its affairs. The chief executive officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith the chief executive officer may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

(3) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheets prepared in the

first instance as at the close of business on the 27th April 1985 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance sheets shall be got audited and certified by the chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

A copy each of the balance sheets of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheets or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of section 159 of the Companies Act, 1956, and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by section 283 of that Act.

(4) 1. The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the property and assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely :—

- (a) Investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date.
- (b) (i) Government securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the principles laid down in the notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949.
- (ii) The securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher.
- (iii) Where the market value of any Government security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security in respect of which the principal is payable in instalments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such an amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors.

- (c) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period.
- (d) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors.
- (e) Premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value.
- (f) Furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable.
- (g) Advances including bills purchased and discounted, book debts and sundry assets, will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank. Hereafter the advances, including portions thereof will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery."

II. Liabilities for purposes of this scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

III. Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date.

In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regards the valuation of any asset and/or the classification of any advance and/or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, whose opinion shall be final, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of this scheme.

It shall be competent for the Reserve Bank in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

(5) In consideration of the transfer of the property and the assets of the transferor bank to the transferee bank the transferee bank shall discharge the liabilities of the transferor bank to the extent mentioned in this and the following clauses, namely:—

(a) Any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits together with interests, if any, accrued thereon up to the prescribed date and all other outside liabilities as on the prescribed date excluding deposits shall be paid or provided for in full.

EXPLANATION

For the purpose of this paragraph, interest payable on a deposit up to the prescribed date shall be regarded as part of the concerned deposit.

(b) In respect of every savings bank account or current account or any other deposit including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposit by whatever name called with the transferor bank and every other account not covered by clause (a), including interest to the extent payable under this scheme, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder (s) thereof crediting thereto the pro rata share available in respect of each of the accounts out of the assets referred to in paragraph (4) as valued for the purposes of this scheme on the prescribed date, after excluding from the said assets as so valued for advances considered not readily realisable or bad or doubtful of recovery any asset or portion of an asset not valued on the prescribed date and any amount needed for the payments or provisions mentioned at clause (a) above and after adding to the said assets as so valued the aggregate amount of the payments made in terms of clause (a) (i) of paragraph 2 of the moratorium order dated the 27th April 1985 issued to the transferor bank :

Provided that any payment made from a deposit account on, or after the close of business on 27th April 1985 and before the prescribed date, shall be reckoned towards the amount to be credited under this sub-paragraph and, accordingly the amount to be credited shall be the pro rata share less the amount of such payment :

Provided further that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account it may with the approval of the Reserve Bank, withhold the credit to be made in that account in terms of clause (b) above till the transferee bank is able to ascertain the correct balance in such accounts.

EXPLANATION

The term 'pro rata' shall, insofar as it occurs in this paragraph, mean in proportion to the respective amounts remaining due as at the close of business

on the 27th April 1985 (together with interest payable up to the date immediately preceding the prescribed date) and shall, insofar as it occurs elsewhere in this scheme, mean 'in proportion to the respective amounts remaining due at the time of the payment or distribution.'

(c) After the credits referred to in clause (b) above have been afforded, the transferee bank shall, with the least possible delay but in any case not later than three months from the prescribed date, furnish to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter referred to as the Corporation) a list complying in all respects with the requirements of sub-section (1) of section 18 of that Act and thereafter whenever amounts referred to in sub-section (2) of section 18 of that Act are received from the Corporation, the transferee bank shall credit each of the accounts referred to in clause (b) above, within seven days from the date or dates on which the amounts are received, to the extent of the sums due to that account in accordance with sub-section (2) of section 18 of that Act:

Provided that—

(a) if any account referred to in clause (b) has been closed or has matured for payment at the time when any amount for credit to that account is received from the Corporation, the payments to the person entitled to the said amount shall be made by the transferee bank in cash;

(b) in case the person entitled to any amount referred to in clause (b) cannot be found or is not readily traceable, provision for the amount due to such person shall be made and accounted for separately on the books of the Corporation itself and it shall not be necessary for the Corporation to pay the amounts to the transferee bank unless the person entitled to the amount is found or traced and the Corporation has decided to make the payment in respect of that person through the transferee bank.

(c) On the prescribed date, the entire amount of the paid up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank and the rights of the members of the transferor bank shall, in relation to the transferee bank, be as provided for in paragraph (6) below:

(6) In respect of

(a) every account mentioned in clause (b) of the preceding paragraph, the balance in the account, if any, remaining uncredited in terms of that clause and clause (c) and

(b) every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date and/or amount paid on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of clause (i) below

shall be treated as a collection account and may be entered as such in the books of the transferee bank and payments against the account shall be made in the following manner, namely;

(i) (a) the transferee bank shall, in the first instance, call upon every person who on the prescribed date was registered as the holder of a deferred share in the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any and thereafter, if it is found to be so necessary every person who was as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares or the calls in arrears, if any;

(b) the transferee bank shall take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under clause (a) together with interest at six per cent per annum for the period of the default.

(ii) the transferee bank shall in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery", or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date in terms of paragraph (4) above, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, provided, however, that if the amount of a debt or asset exceeds Rs. 50,000, the transferee bank shall not except with the approval of the Reserve Bank of India :

(a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset.

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(iii) the transferee bank shall in addition take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promotor, director, manager or other officer of the transferor bank under section 45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with section 45H thereof and also with section 543 of the Companies Act, 1956;

(iv) the transferee bank may out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, make payment or provision in respect of any contingent liability to the extent that the provision made therefor under paragraph (5) (a) proves to be inadequate, as also with the prior approval of the Reserve Bank, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of paragraph (4) above and has arisen or been discovered on or after the prescribed date.

(v) the transferee bank shall out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above after deducting therefrom the expenditure incurred for the purpose and, with the approval of the Reserve Bank of India, such other expenses as may be considered reasonable and the amount appropriated therefrom in terms of clause (iv) above, or out of the balance, if any, which may be available from out of the provision in respect of contingent liabilities as reckoned for the purposes of this scheme after the extent of such liabilities has finally been ascertained,

(a) pay to the Corporation the amount received by the transferee bank from the Corporation under sub-section (2) of section 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and the amount, if any, provided for by the Corporation, and

(b) pay, in the case of depositors in respect of whom no amounts have been received by the transferee bank from the Corporation, the amounts due in respect of the collection accounts, and in the case of depositors in respect of whom any amounts have been received by the transferee bank from the Corporation or have been provided for by the Corporation the balance if any due to them in their collection accounts after the amounts due from the said accounts to the Corporation in respect of the payment made or provided for by the Corporation have first been paid in accordance with the provisions of sub-clause (a) above :

Provided that the amount due to the Corporation shall if it becomes necessary so to do, be provided for in the books of the transferee bank and be paid to the Corporation in the manner specified in clause (b) of regulation 22 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961 :

Provided further that the transferee bank shall make the payments referred to in clause (b) above,

(i) if the corresponding or similar account mentioned in clause (b) of paragraph (5) has not been closed or has not matured for payment, by credit to that account, and

(ii) if the said account has been closed or has matured for payment, in cash;

(vi) The amounts due to the Corporation in terms of sub-clause (a) of clause (v) above and the amounts due to the collection accounts of the depositors in terms of sub-clause (b) of that clause shall rank equally among themselves, and if they cannot be paid in full shall abate in equal proportions ;

(vii) After the payments referred to in clause (v) of this paragraph have been made or provided for in full, the transferee bank shall, out of the balance of the amounts referred to in clause (v) which may be available to it, make payments pro rata towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders, of the transferor bank in the manner and to the extent specified below :

(a) in the first place, the amounts, if any due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;

(b) in the second place, the amounts, if any, due to the accounts of the former ordinary shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made; and thereafter

(c) in the third place, the amounts, if any, due to the accounts of the former deferred shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;

(d) after all the amounts mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) above have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed pro rata among the former ordinary shareholders of the transferor bank .

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(viii) the amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in this scheme;

(ix) on the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in clause (ii) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any amount or amounts determined in the light of that valuation after deducting therefrom first any sum necessary for meeting the liabilities referred to in clause (iv) of this paragraph which may remain unsatisfied as on that date in the order and the manner provided in clauses (vi), (vi) and (vii) above.

(x) The transferee bank shall invest such moneys realised on account of items mentioned in the preceding clauses (i), (ii) and (iii) as are not likely to be required by it for immediate payment, in interest bearing deposits with itself or with any other bank or banks, in such manner and for such periods as may be appropriate having regard to the facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank of India may direct. The interest accrued shall be applied for meeting the liabilities referred to in clauses (iv), (v), (vi) and (vii) in the manner indicated therein.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest shall be paid in respect of the new accounts opened with the transferee bank in terms of paragraph (5) and credited in accordance with the provisions of that or the next succeeding paragraphs only at such rates as the transferee bank may allow.

(8) No depositor or other creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against

the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

(9) No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee or the transferor bank for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this scheme.

(10) All the employees of the transferor bank other than those specified in the schedule referred to in the succeeding paragraph shall continue in service and be deemed to have been appointed by the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as were applicable to such employees immediately before the close of business on 27th April 1985.

Provided that the employees of the transferor bank who have, by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the date on which this scheme has been sanctioned by the Central Government, intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules of authorisations of the transferor bank immediately before the close of business on 27th April 1985.

Provided further that the transferee bank shall in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank be deemed also to have taken over the liability for the payment of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(11) The persons specified in the schedule annexed to this scheme shall on the prescribed date cease to be the employee of the transferor bank and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any agreement or contract, the persons so specified shall be entitled to and only to such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible to them under the rules or authorisations of the transferor bank immediately before the close of business on 27th April 1985.

Provided that the compensation, if any, for the loss of employment, so far as it relates to the unexpired portion of any contract of service, shall be such and only such as may be determined by the Reserve Bank (whose determination in this respect shall be final and binding).

Provided further that nothing herein shall be deemed to prevent the transferee bank from re-employing any person whose name has been specified in the schedule annexed to this scheme in such capacity and on such terms and conditions as the transferee bank may deem fit.

574 3/1/85

(12) The transferee bank shall, on the expiry of a period not longer than three years from the date on which this scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience on the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank.

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure of principles to be adopted for the fixation of the pay of the employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(13) The trustees or administrators of any provident fund constituted for the employees of the transferor bank or as the case may be the transferor bank shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustee of the employees provident fund constituted for the transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all the monies and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank.

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect, or default done before the prescribed date.

(14) The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of this scheme.

(15) The transferee bank shall furnish to the shareholders of the transferor bank a statement of affairs of the transferor bank in such form and at such periodical intervals as the Reserve Bank of India may specify in this behalf. The sending of such statements shall be discontinued when so directed by the Reserve Bank.

(16) Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by pre-paid ordinary post to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of forty-eight hours after it has been posted. Any notice or communication which is of general interest shall be advertised in addition in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

(17) If any doubt arises in interpreting any of the provisions of this scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India and its opinion shall be conclusive and binding on both the transferee and

transferor banks, and also on all the members, depositors and other creditors and employees of each of these banks and on any other person having any rights or liability in relation to any of these banks.

(18) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this scheme, the Central Government may issue to the transferor and the transferee banks or to either of them such directions not inconsistent with this scheme as may appear to the Central Government, after consulting the Reserve Bank of India, to be necessary or appropriate for the purpose of removing the difficulty.

[F. No. TS/1/85-B.O.III]
S. M. KELKAR, Addl. Secy.

SCHEDULE

Schedule attached to and forming part of the scheme for the amalgamation of the Miraj State Bank Ltd., as sanctioned by the Central Government under sub-section (7) of section 48 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

Name of the employee	Designation in the transferor bank
----------------------	------------------------------------

1. Shri V. Krishnan	
Assistant General	
Manager	